दैनिक जागरण

लगन का अर्थ है 19 बार असफल होकर 20वीं बार सफल होना

आतंक का एक और चेहरा

अनुशासित जीवनशैली और शांतिप्रिय वातावरण के लिए मशहूर न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर भीषण गोलीबारी करके जिस तरह करीब 50 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया वह हर लिहाज से एक आतंकी घटना ही है। यह भयावह आतंकी हमला जिस श्वेत चरमपंथी ने किया वह खुद तो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, लेकिन उसे यह शिकायत है कि श्वेत आबादी वाले देशों में शरणार्थी क्यों बसते जा रहे हैं? वह केवल मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति नफरत से भी भरा हुआ है। नफरत से भरे इस श्वेत चरमपंथी को उचित ही आतंकी कहा जा रहा है। उसमें और जेहादी आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाने वाला हमलावर जेहादी आतंकवाद के चलते इस्लाम के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल के कारण ही मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत से ग्रस्त हुआ होगा। दुनिया में जो लोग भी इस तरह का माहौल बना रहे वे जेहादी आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमजोर करने के साथ ही नए तरह के आतंकी पैदा करने का ही काम कर रहे हैं। नफरत का जवाब नफरत से देने से तो दुनिया तबाही की ओर ही बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलियाई हमलावर ने न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर कहर ही नहीं बरपाया, बल्कि निर्दोष-निहत्थे लोगों को मारने के अपने कृत्य का सोशल मीडिया पर प्रसारण भी किया। साफ है कि वह अपने जैसे लोगों को अपनी करतूत से अवगत कराना चाहता था।

यह पहली बार नहीं जब प्रवासियों और खासकर मुसलमानों के प्रति द्वेष से भरे किसी श्वेत चरमपंथी ने आतंकी वारदात की हो। पश्चिमी देशों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन देशों में सिर उठा रहे श्वेत चरमपंथी तत्व अश्वेतों के प्रवेश के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति हिंसक व्यवहार भी कर रहे हैं। इस तरह के मामले यही बताते हैं कि जेहादी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सही तरह से नहीं लड़ी जा रही है। यह सही है कि किस्म-किस्म के आतंकी मत-मजहब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके चलते उस मत-मजहब को दोष देना तो समस्या को और गंभीर बनाना ही है। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेहादी आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम किसी मत-संप्रदाय को कठघरे में खड़ा करते न दिखें। इस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब एक ओर जहां जेहादी आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सतर्कता बरती जाए वहीं दूसरी ओर उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो या तो जेहादी संगठनों को पालने-पोसने का काम कर रहे हैं या फिर उनका खुले-छिपे तरीके से समर्थन करते हैं। यह विडंबना ही है कि ऐसे ही कुछ लोग न्यूजीलैंड में आतंकी हमले पर संवेदना जताने का दिखावा कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह सही कहा कि विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक समाज में नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। दुख की इस घड़ी में भारत को न्यूजीलैंड के साथ इसलिए और दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां की संसद ने पुलवामा की आतंकी घटना की आगे बढ़कर निंदा की थी।

और बढ़ानी होगी सजगता

इन दिनों बिहार में शहरों से लेकर गांवों तक आग लगने की घटनाओं का एकदम से बढ़ जाना चिंता की बात है। कह सकते हैं कि इस मौसम में आग का खतरा कुछ ज्यादा ही रहता है। साल भर में होनेवाली आग की घटनाओं में से साठ प्रतिशत से ज्यादा मार्च से जून माह के बीच होती हैं। लेकिन देखा जाए तो आग से निपटने के लिए अभी शासन स्तर पर और सजगता की जरूरत है। वैसे अग्निशमन विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास जारी है। फिर भी फायर फाइटिंग की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं कही जा सकती। इसे भरपूर संसाधनों से लैस करने के साथ ही उचित प्रशिक्षण की भी दरकार है। अभी अग्निशमन विभाग चालक और पानी की समस्या से जूझ रहा है। कई अग्निशमन केंद्रों के पास तो वाटर टैंक ही नहीं हैं। उन्हें पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। शहरों में भले ही यह समस्या कठिन नहीं दिखती, लेकिन दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह आग पर काबू पाने के बाद अग्निशमन दस्ते को वाहन के टैंक में पानी भरने के लिए वापस जिला मुख्यालय या फिर पास के किसी पीएचईडी पंप पर जाना पड़ता है। यह एक बड़ी समस्या है, जिसका शीघ्र निदान होना चाहिए। अग्निशमन विभाग को भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा। दरअसल बिल्डिंग निर्माण से पहले नक्शा पास कराते वक्त आग से बचाव के लिए उपकरण रखने की शर्त पर विभाग एनओसी जारी कर देता है। जबकि निर्माण के बाद अधिकतर बिल्डिंग में अग्निशमन के उपकरण लगाए ही नहीं जाते। लेकिन विभाग दोबारा इनका भौतिक सत्यापन करना जरूरी नहीं समझता। इसी का फायदा उठा बिल्डर नक्शे के वक्त ली गई एनओसी को दिखाकर मकान बेच देते हैं। खरीदार को असलियत तब पता चलती है, जब उसके भीतर आग लगने की घटना सामने आती है। यह एक बड़ी लापरवाही है। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही आपदा के समय स्थानीय सहयोग के लिए नागरिक समितियों का गठन किया जाना भी आवश्यक है।

अतीत के अध्ययन का उचित तरीका

प्रो. मक्खन लाल

यह मानना कि पुरातत्व और लिखित साक्ष्य ही अतीत को जानने का एकमात्र साधन हैं, न केवल अनुचित है, बल्कि सभ्यताओं और संस्कृतियों की जटिलताओं की अनदेखी भी है

भारत में पिछले तीस वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक अयोध्या का मामला रहा है। इसने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। यहां तक कि यह क्रमिक सरकारों के भाग्य का फैसला भी कर रहा है। इसमें शामिल मुद्दा काफी हद तक स्पष्ट है। हिंदुओं का कहना है कि बाबरी मस्जिद जिस स्थान पर थी वह भगवान राम की जन्मभूमि है और मस्जिद बाबर के आदेश से 1528 में मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई। इस दावे के विरोधियों का कहना है कि इसके लिए कोई सुबूत नहीं है। जाहिर है अयोध्या का मुद्दा सिर्फ एक साधारण मंदिर या मस्जिद का मामला नहीं रहा है, बल्कि एक पवित्र स्थल, पावन क्षेत्र, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संदर्भ में भी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मध्यस्थता से इस मुद्दे को सुलझाते समय उसे अधिक व्यापक संदर्भ में संबोधित किया जाना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान को चिन्हित करने के लिए समय-समय पर वहां मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाता रहा। वहां अंतिम बार 11वीं शताब्दी में एक गढ़वाल राजा द्वारा मंदिर निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि उस मंदिर को मुगल शासक बाबर के सेनापति ने 1528 में अपने अभियान के दौरान नष्ट कर दिया और वहां एक मस्जिद बनाई थी। हिंदू तब से इस स्थान को वापस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करते हुए भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकें।

जहां एक ओर लोगों और धर्मगुरुओं के बीच दावों- प्रतिदावों के बीच अदालती मामलों की सुनवाई जारी रही वहीं दूसरी ओर इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और राजनीतिक नेताओं के दावों की वैधता को लेकर बहस जारी रही। इसने सभी को बिना किसी रोक-टोक के दावों को गलत साबित करने और खारिज करने का अवसर दिया। विरासत के मुद्दे पर कई साल पहले वेनेजुएला के बारक्यूसिमेतो शहर में विश्व पुरातत्व कांग्रेस (डब्ल्यूएसी) में पारित प्रस्ताव एक उल्लेखनीय दस्तावेज है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 'विश्व पुरातत्व कांग्रेस स्वीकार करता है कि पवित्र स्थलों की पहचान और संरक्षण दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। इसके लिए विश्व पुरातत्व कांग्रेस के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि विरासत से संबंधित मुद्दों का पता लगाया जा सके। साथ ही पवित्र स्थलों, पवित्र स्थानों, पवित्र क्षेत्रों आदि पर वास्तविक सहमति बनाई जा सके।'

इस संदर्भ में विश्व पुरातत्व श्रृंखला (वन वर्ल्ड आर्कियोलॉजी सीरीज) में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए जो स्पष्ट रूप से पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और दुनिया के लोगों के लिए भी मानदंड तय करते हैं। उस श्रृंखला के संपादक प्रो. पीटर अक्को एक पुस्तक 'सेक्रेड प्लेसेस, सेक्रेड स्पेसेस' की भूमिका में लिखते हैं, 'डब्ल्यूएसी का संबंध हमेशा अतीत के दस्तावेजीकरण और उसे प्रस्तुत करने से ही नहीं रहा है, बल्कि इससे भी अधिक यह पता लगाना रहा है कि लोगों के अतीत कैसे रहे और यह भी कि परिवर्तन क्यों और कैसे हुए तथा जो समाज, संस्कृति और परंपराएं आज मौजूद हैं उसे कैसे प्रभावित किया।' पवित्र स्थल, पवित्र क्षेत्र इत्यादि लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस बात को इतिहासकारों, मानववैज्ञानिकों और समाजविज्ञानियों तथा अन्य सभी को ध्यान में रखना होगा। हमें यह स्वीकारना होगा कि किसी विशेष काल और परिस्थितियों की वजह से पवित्र स्थान, पवित्र क्षेत्र आदि की उत्पत्ति और पहचान होती है और मानव समाज में उसकी यह पहचान चिरस्थायी हो जाती है। ऐसे सभी स्थान और क्षेत्र लोगों के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे पवित्र स्थलों और क्षेत्रों के महत्व को नकारना या कमतर करना बेमानी होगा। सभी मानव समुदायों ने अतीत और वर्तमान में पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों, पहाड़ों, नदियों को विशेष महत्व दिया है और इस महत्व को स्थाई और परिलक्षित करने के लिए स्मारकों/संरचनाओं का निर्माण किया या कभी-कभी नहीं भी किया। ऐसे सभी स्थानों को जानने के लिए पुरातत्व या लिखित इतिहास ही एकमात्र साधन नहीं हैं, स्थानीय परंपराएं, आस्था और लोगों की मान्यताएं और प्रथाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

अवधेश राजपूत

कोई स्थान या पृथ्वी क्षेत्र, नदी, समुद्र, पहाड़ आदि इसलिए पवित्र हैं, क्योंकि मनुष्य इन्हें पवित्र मानते हैं। पृथ्वी के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पवित्र स्थानों के बारे में और पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानने के विभिन्न तरीके हैं। कुछ तरीके वैज्ञानिक हैं तो कुछ पारंपरिक या पौराणिक और कुछ आध्यात्मिक हैं। जानने का एक तरीका दूसरे की वैधता को नकारता नहीं है। यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक ज्ञान और प्रभाव को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पारंपरिक स्वदेशी तरीकों को जानने की वैधता को भी मान्यता दी जानी चाहिए। अतीत के अध्ययन के लिए कोई सरल नुस्खा नहीं है। यह मानना कि पुरातत्व और लिखित साक्ष्य ही अतीत को जानने का एकमात्र साधन हैं, न केवल अनुचित है, बल्कि कई साक्षर और गैर-साक्षर सभ्यताओं और संस्कृतियों की जटिलताओं की अनदेखी भी है। किसी भी समाज को और उसके लोगों को अतीत से दूर ले जाने का अर्थ है उन्हें अपनी परंपराओं और उनके विश्वासों से दूर करना और इस प्रकार उनके वर्तमान तथा भविष्य को उनके नियंत्रण से परे रखना। पवित्र स्थलों और क्षेत्रों के स्वामित्व का सवाल अन्य लोगों या अन्य धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों के द्वारा घुसपैठ के संदर्भ में भी उठता है। भूमि के एक टुकड़े के नुकसान को सिर्फ एक भौतिक नुकसान के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक अभाव के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही प्रभावित लोगों को उनकी परंपरा, संस्कृति और धर्म से वंचित किए जाने के रूप में भी देखा जाता है।

अयोध्या विवाद के संदर्भ में कई लोग यह तर्क देते रहे हैं कि वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को संस्कृति और धर्म सहित अन्य सभी चीजों पर वरीयता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में हम सब मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन पिछले कई दशकों के अध्ययन यह दिखाते हैं कि 'यह धारणा कि विश्व संस्कृति का सृजन केवल प्रौद्योगिकी में सुधार और विज्ञान की सार्वभौमिक शिक्षा के माध्यम से ही बनाया जा सकता है पूर्णतः अविवेकी है। विज्ञान आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम सभी अपनी संस्कृतियों के अतीत के साथ आगे बढ़ते हैं और यह हमारे विचारों तथा अनुभवों का संचय है। यह हमारी शिक्षा और दैनिक जीवन के माध्यम से प्रेषित होता है, जो हमारे विचारों को अर्थ और कार्यों को पैटर्न एवं उद्देश्य देता है। ऐसा नहीं है कि हम अतीत में रहते हैं, लेकिन हम इसके द्वारा परिभाषित होते हैं। विज्ञान अपने स्वयं के इतिहास को भूल सकता है, लेकिन एक समाज ऐसा नहीं कर सकता।

(लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, दिल्ली के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

प्रयोगों का शिकार बनी टीम इंडिया

शिवेंद्र कुमार सिंह

विश्व कप की तैयारी गलत नहीं, लेकिन उन तैयारियों और वनडे सीरिज की रणनीति में संतुलन भी होना चाहिए

ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज के आखिरी और पांचवें मैच के पहले ही बिशन सिंह बेदी ने कहा था कि वनडे मैचों में धौनी टीम के आधे कप्तान होते हैं और उनकी गैरमौजूदगी में विराट कोहली 'रफ' दिखाई देते हैं। हुआ भी ऐसा ही। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से पिछड़ने के बाद अप्रत्याशित तरीके से लगातार तीन वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। दिल्ली में खेले गए आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 35 रन से हरा दिया। 273 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम 237 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दोनों ही टीमों के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए सीरीज से पहले किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को उसी के घर में हराकर जाएगी। पिछले दो साल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली बार किसी वनडे सीरीज में जीत मिली है। जाहिर है अब बिशन सिंह बेदी की ओर से कही गई बात की समीक्षा का वक्त है। क्या वाकई आखिरी दोनों मैच में धोनी को आराम देने की जरूरत थी? उन्होंने 2019 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर एक के बाद एक प्रयोग को भी बेवजह बताया था। हैरत नहीं कि इन्हीं प्रयोगों के तहत धौनी को आराम दिया गया हो।

धौनी ने एक ऐसी टीम की कप्तानी की है जिसमें एक वक्त पर कई पूर्व कप्तान-सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले खेला करते थे। मुश्किल परिस्थितियों में वह इन सभी की सलाह लेते थे। उनमें अपना 'क्रिकेटिंग ब्रेन' भी जबरदस्त था। धीरे-धीरे उन्होंने उसे इतना विकसित किया कि वह बड़े फैसले और बड़े बदलाव खुद करने लगे। इसका ही नतीजा था कि धौनी की कप्तानी में टीम ने 2011 का विश्व कप जीता। इससे पहले टी-20 विश्व कप उनकी कप्तानी में भारत जीत ही चुका था। वह भारत के सफलतम कप्तान बने। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, फिर वनडे में टीम की कप्तानी छोड़ी। वह विराट कोहली की कप्तानी में सीमित ओवरों का मैच खेलते रहे। माना जा रहा कि वह 2019 विश्व कप के बाद वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। आज विराट कोहली उस जगह पर हैं जहां कभी धौनी हुआ करते थे। विराट कोहली धौनी से सलाह लेते रहते हैं जिसका उन्हें फायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि विराट कोहली अपना 'क्रिकेटिंग ब्रेन' विकसित नहीं कर रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय के साथ मैच दर मैच उनमें विकसित होती रहेगी, लेकिन जब धौनी मैदान में होते हैं तब विराट को उनकी सलाह का फायदा मिलता है। गावस्कर इसे दुआ मानते हैं। एक दिन वह भी आएगा जब विराट बिना धौनी के मैदान में उतरेंगे लेकिन जब तक धौनी खेल रहे हैं तब तक वह उनसे कुछ और बारीकियां सीख सकें तो उनके साथ पूरी टीम को फायदा होगा। भले ही धौनी को उनकी बल्लेबाजी के लिए घेरा जाता हो, लेकिन विकेटकीपिंग में आज भी कोई उनके आस-पास नहीं है। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में शुमार हैं। अगर उनके 'इनपुट्स' की बात की जाए तो इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सीमित ओवरों के मैच में विराट बाद के ओवरों में बाउंड्री की तरफ फील्डिंग करने चले जाते हैं। ऐसे में धोनी ही 'फील्ड प्लेसमेंट' करते हैं। बल्लेबाजों की सोच को भांपते हुए वह बदलाव करते रहते हैं। विकेट के पीछे से वह इन गेंदबाजों को लगातार सलाह देते हैं कि वे कहां गेंद फेंके?

ये वे बातें हैं जो विराट कोहली को मदद करती हैं और मैच के नतीजों पर असर डालती हैं। आखिरी दो वनडे मैचों में धौनी की जगह ऋषभ पंत ने कीपिंग की। अभी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन पंत ने जिस तरह विकेट के आगे और पीछे गलतियां कीं उससे धौनी की कमी महसूस हुई। यह कमी विराट कोहली को भी समझ आई होगी। यह साफ दिख रहा कि मौजूदा सीरीज के मैचों को लेकर रणनीति बनाने के बजाय विश्व कप के लिहाज से कुछ ज्यादा ही प्रयोग किए गए। विश्व कप की तैयारी करना गलत नहीं हैं, लेकिन उन तैयारियों में और मौजूदा सीरीज के मैचों की रणनीति में जो संतुलन होना चाहिए वह दिखाई नहीं दिया।

वनडे सीरीज में लगभग सभी मैचों में टीम इंडिया अपनी 'फुल स्ट्रेंथ' के साथ नहीं उतरी। कई मैचों में सिर्फ दो तेज गेंदबाज दिखाई दिए। आखिरी मैच में तीन तेज गेंदबाज थे तो एक बल्लेबाज कम हो गया। टी-20 सीरीज में विराट कोहली ने तीन-तीन विकेट कीपर मैदान में उतार दिए थे। नंबर चार की समस्या जैसे की तैसे बनी रही। कोच रवि शास्त्री एक नई 'थ्योरी' लेकर आए हैं कि वह विश्व कप में विराट कोहली को नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए भी कह सकते हैं। अंबाती रायडू, केदार जाधव, विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों के रोल को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं बन पाई और यह इंतजार और लंबा हो रहा कि ऋषभ पंत अपने बल्ले से कुछ कमाल दिखाएंगे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | मतदाता संख्या में वृद्धि

(आम चुनाव के मतदाता, संख्या करोड़ों में)

स्रोत : भारत निर्वाचन आयोग

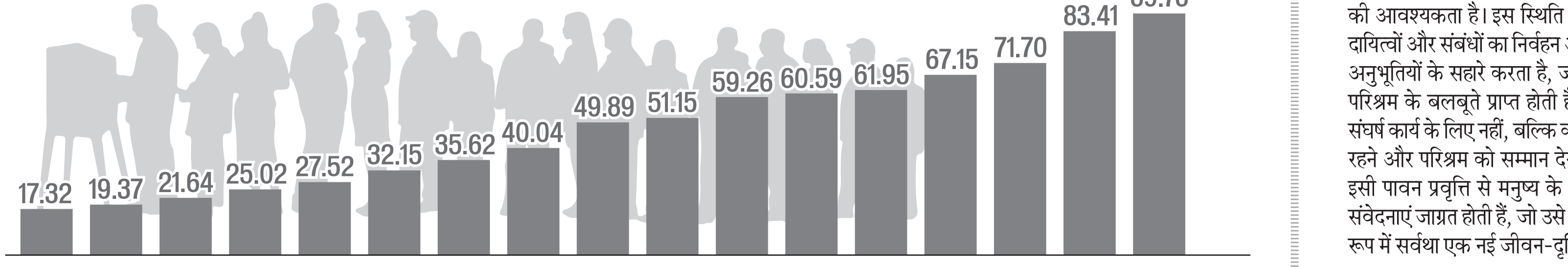

ऊर्जा

परिश्रम

इस दुनिया में संघर्षशील व्यक्ति के पास सबसे अच्छे अनुभव होते हैं। इसलिए संघर्ष और परिश्रम से हमेशा लगाव रखना चाहिए। अपेक्षित प्रतिफल न मिलने की स्थिति में निराश और हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है या हो सकता है, उससे संतुष्ट होने की प्रवृत्ति तब ही बनती है, जब संघर्ष के दौरान हम कभी यह नहीं सोचेंगे या चाहेंगे कि हमें यह नहीं मिला या हमें वह मिलना चाहिए। जब हमारे सामने इतना बड़ा कटु सत्य है ही कि जीने के लिए किसी न किसी तरह का परिश्रम करना है तो क्यों न हम परिश्रम को गुणात्मक और आनंददायक बनाते चलें।

जीवन में कठिन लगने वाली स्थितियों-परिस्थितियों के दौरान भी हमारे पास वास्तव में आनंदित होने के बहुत से तरीके होते हैं। हमें कठिनाई और समस्याओं से जूझते हुए सर्वप्रथम इनकी सहायता लेनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तरीका है यह कि हम जो भी काम करते हैं, उसके प्रति लगाव रखें। काम के दौरान किया जानेवाले परिश्रम की महत्ता का ध्यान रखें। काम के बोझ के कारण या काम के बीच आने वाली बाधाओं से खुद को दुखी करने के बजाय यह सोचें कि हमें अपने परिश्रम का सम्मान करना है। हम अपने परिश्रम का सम्मान करेंगे तो काम से संबंधित बाधाएं तो समाप्त होंगी ही साथ ही बाधाओं के कारण उपजा अलगाव भी मिट जाएगा। कुछ दिनों तक यदि हम अपने कार्यों को इस भावना के साथ करेंगे तो निश्चित रूप में हमारे भीतर एक नई वैचारिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। यह स्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर करती है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने दायित्वों को श्रेष्ठ तरीके से निभाने के लिए ऐसे ही आध्यात्मिक प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने कार्यों, दायित्वों और संबंधों का निर्वहन अपनी स्वयं की परिपक्व अनुभूतियों के सहारे करता है, जो उसे अपने संघर्षों एवं परिश्रम के बलबूते प्राप्त होती हैं। जीवन में वास्तविक संघर्ष कार्य के लिए नहीं, बल्कि कार्य के दौरान आनंदमग्न रहने और परिश्रम को सम्मान देने के लिए होना चाहिए। इसी पावन प्रवृत्ति से मनुष्य के भीतर उसकी स्वानुभूत संवेदनाएं जाग्रत होती हैं, जो उसे मानसिक और आत्मिक रूप में सर्वथा एक नई जीवन-दृष्टि प्रदान करती हैं।

विकेश कुमार बडोला

चलन से बाहर होते एटीएम

कपिल अग्रवाल

देश में जिस तरह कैशलेस इकोनॉमी का दायरा बढ़ रहा है उससे 2020 तक डेबिट-क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम एवं स्वाइप मशीनें चलन से बाहर हो सकती हैं

बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम के संबंध में कुछ विशेष दिशानिर्देश जारी किए थे जिनके मुताबिक सभी बैंकों को नए सुरक्षा फीचर्स के अलावा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को उन्नत करना है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी कैश डिलिवरी वैन के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी नए नियम लागू कर दिए हैं। अनुमान है कि इन दिशानिर्देशों से बैंकों एवं एटीएम उद्योग पर लगभग 38 अरब रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा और रिजर्व बैंक के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस अतिरिक्त लागत का बोझ ग्राहकों पर न डालकर बैंकों तथा सेवा प्रदाता कंपनियों को वहन करना होगा। पहले से ही बदहाल बैंक एवं एटीएम उद्योग इसके लिए तैयार नहीं हैं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पिछले पांच साल से एटीएम उद्योग को शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है।

देश में एटीएम दो प्रकार के हैं। एक वे जिन्हें बैंकों ने खुद स्थापित किए हैं और दूसरे वे जो सेवा प्रदाताओं से कमीशन के आधार पर यानी ठेका पद्धति पर लिए गए हैं। लागत में भारी भरकम वृद्धि के बावजूद कमीशन न बढ़ाए जाने से ठेके वाले अधिकांश एटीएम घाटा झेलकर बंद हो चुके हैं और बैंकों के भी अपने कई एटीएम खराब पड़े हैं। बिजली बिल, जगह के बढ़ते किराए, रखरखाव एवं नए नोटों के अनुरूप रद्दोबदल में आ रहे खर्चो को देखते हुए बैंक अब इन्हें दुरुस्त कराने से परहेज कर रहे हैं। खबर है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए बीते चार माह के दरम्यान कई बार एटीएम उद्योग के संगठन और भारतीय बैंक परिसंघ के प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय एवं रिजर्व बैंक से गुहार लगा चुके हैं।

एटीएम यानी ऑटोमेटिड टेलर मशीन एक गूढ़ टेक्नोलॉजी वाला उद्योग है जिसमें मशीन बनाने, लगाने एवं चलाने वाली कंपनियों से लेकर मशीन में नगदी डालने वाली कंपनियों के अलावा विभिन्न प्रकार के सहायक स्टाफ, तकनीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर्स, सुरक्षाकर्मी आदि से संबंधित सेवा प्रदाता कंपनियां शामिल हैं। पिछले तीन साल में मुद्रा के लेन-देन, जमा-निकासी एवं भुगतान आदि के तौर-तरीके बदले हैं और खासकर शहरों तथा महानगरों में शिक्षित वर्ग एटीएम तक जाने के बजाय घर बैठे विभिन्न डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने को प्राथमिकता दे रहा है। एटीएम का ज्यादा उपयोग अब कमजोर एवं अल्प शिक्षित तबका ही कर रहा है। शहरों एवं महानगरों में डिजिटल लेन-देन के चलन बढ़ने से एटीएम की उपयोगिता बहुत घट गई है और अब अधिकांश एटीएम कई-कई दिनों तक इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं।

दरअसल समय के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर एटीएम की उपयोगिता अब खत्म होती जा रही है और अधिकांश देशों में मशीनें बहुत कम संख्या में केवल बैंक परिसरों एवं मुख्य व्यावसायिक परिसरों तक सीमित होकर रह गई हैं। जापान, फ्रांस एवं अमेरिका जैसे उन्नत मुल्कों में तो इनका स्थान कैशलेस इकोनॉमी ने ले लिया है। हमारे देश में भी कैशलेस इकोनॉमी का दायरा बढ़ता जा रहा है और नीति आयोग का अनुमान है कि 2020 तक डेबिट-क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम एवं पीओएस यानी स्वाइप मशीनें पूर्णतः चलन से बाहर हो जाएंगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आपसी सौहार्द से बने राम मंदिर

ए सूर्यप्रकाश ने अपने आलेख 'मध्यस्थता को दीजिए एक मौका' में राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता वाली बात को एक अच्छी पहल मानते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर बनाने को हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए हितकारी माना है। चूंकि कोर्ट का निर्णय दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में अयोध्या की विवादित जन्म-भूमि पर राम मंदिर का निर्माण सामाजिक सौहार्द के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए आपसी बातचीत से राम मंदिर निर्माण का ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, क्योंकि पाक पोषित आतंकवाद के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई को लेकर देश के अंदर जो खिंचावपूर्ण माहौल बन रहा है, उसे देखते हुए भी यह जरूरी है कि आपसी सहमति और सौहार्द के साथ राम मंदिर निर्माण की पहल हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस फकीर इब्राहिम कलिफुल्ला की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति दोनों पक्षकारों से बात करके राम मंदिर निर्माण का ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करे, जिससे दोनों पक्ष सहमत हों। यदि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई सहमति बन जाती है तो यह देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

pandeyvp1960@gmail.com

अब न्यूजीलैंड में भी आतंक

अब तक सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले देश न्यूजीलैंड में भी आतंकवाद ने दस्तक दे दी है। वहां की दो मस्जिदों में आतंकी ने गोलीबारी करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस हमले में बाल-बाल बची है। विश्व में भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। भारत ने अनेक बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन दुनिया के कई देशों ने भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं को हल्के में लिया। चीन भी अपने सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाता रहा है। वह अपने देश में उइगर उग्रवादियों पर तो कठोरता से पेश आता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति में आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को वीटो कर देता है। आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है।

सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी

अब जनता की बारी

चुनाव की घोषणा होने के बाद अब नेताओं की पारी समाप्त और जनता की बारी आ गई है। कोई हाथ जोड़ेगा तो कोई पैर छुएगा। कोई काम का वादा करेगा तो कोई हाथों हाथ काम निपटा भी देगा। क्योंकि नेताओं को चाहिए पांच बरस के लिए कुर्सी। वैसे मतदान करना मतदाताओं का अधिकार है। उन्हें सही सरकार चुनने के लिए अपने मत का उपयोग अवश्य करना चाहिए।

mahesh_nenava@yahoo.com

पहले खुद सुधरें

हम चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन खुद को सुधारना नहीं चाहते। अगर किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। हमें चीनी सामानों पर रोक लगाने के लिए अपने देसी उद्योगों को सुधारने की जरूरत है। हमारे उद्योग जब सस्ते एवं टिकाऊ सामान तैयार करने लगेंगे तो कोई क्यों चीनी सामान खरीदना चाहेगा। देश भक्ति और देश के लिए जज्बा सिर्फ बातों में ही नहीं, बल्कि कर्तव्य में भी दिखना चाहिए।

ऋषि भारद्वाज, नोएडा

चीन का विरोध

1962 से लेकर आज तक चीन से भारत को हमेशा धोखा ही मिला है। भारत की इच्छा के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर वीटो पावर का प्रयोग करता है। डोकलाम में सैन्यदल की तैनाती करता है। इतना ही नहीं वह श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान आदि छोटे देशों में निवेश या आर्थिक मदद के नाम पर भारत की घेराबंदी भी करता है। आज लगभग सभी देश उसकी विस्तारवाद नीति से त्रस्त हैं। भारत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, ऐसे में भारत चीन के सामान का बहिष्कार कर उसे आर्थिक चोट पहुंचा सकता है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।